

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वै०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून-दिनांक: ३ु फरवरी, 2009

विषय:- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।  
महोदय

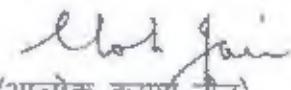
उपर्युक्त विधयक शासनादेश संख्या: ३९५/xxvii(7)/2008 दिनांक १७ अक्टूबर, २००८ के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि का दिनांक १-१-२००६ से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति-२००८ के द्वितीय प्रतियेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/गृ०जी०सी०, १०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आ०२० वेतनमानों से आच्छादित पदों को (छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तार कर्मचारियों जिन्होंने अपने परिवार को दो वर्षों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-२ भाग-२ से४ के मूल नियम-९(२३)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) जिन कर्मचारियों को १ सितम्बर, २००८ से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस राशि को दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय।

(ख) दिनांक ३१ अगस्त, २००८ के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि को ग्रेड वेतन के १० प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा।

३-उपर्युक्त विधयक शासनादेश संख्या ४६०१/१६-११-७९-९-१५३-९९ दिनांक २३ फरवरी, १९८० एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

मरदीय,

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव

संख्या: ५० (१) / xxvii(7) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कौशागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कौशाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला थैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन० आई० री० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव।